IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

रूस-यूक्रेन युद्ध का भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव: संप्रभुता, बहु-संरेखण और वैश्विक दक्षिण नेतृत्व के बीच संतुलन

Dr. Vishal Dubey
Assistant Professor
Mahamaya Rajkiya Mahavidyalaya Sherkot Bijnor

सारांश :

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण ने वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया और एक बार फिर शीत युद्धकालीन विभाजन रेखाओं को सामने ला दिया। इस संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया जिसमें रूस की निंदा से परहेज़, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से विरत रहना, और रूस से तेल आयात में अभूतपूर्व वृद्धि शामिल है वैश्विक समुदाय को आश्चर्यचकित किया है। यह शोध पत्र भारतीय विदेश नीति पर इस युद्ध के बहुआयामी प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह तर्क देता है कि भारत की प्रतिक्रिया 'रणनीतिक स्वायत्तता' और 'बहु-संरेखण' की उसकी दीर्घकालिक विदेश नीति परंपराओं की निरंतरता है, न कि उनसे विच्छेद। रूस के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं, और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आकांक्षा ने भारत की स्थिति को आकार दिया है। साथ ही, भारत ने स्वयं को 'वैश्विक दक्षिण के नेता' और 'शांति स्थापक' के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। हालाँकि, इस रुख ने भारत को पश्चिमी दबाव, द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम, और नैतिक विश्वसनीयता के संकट का सामना करना पड़ा है। यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि युद्ध ने भारत के सिद्धांत-आधारित और हित-आधारित विदेश नीति के बीच के तनाव को उजागर किया है, जिससे भारत को एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को पुनः परिभाषित करने का अवसर और चुनौती दोनों मिली है।

संकेत शब्द : भारतीय विदेश नीति, रूस-यूक्रेन युद्ध, रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण, वैश्विक दक्षिण

परिचय :

फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धारणीयता को चुनौती दी और वैश्विक व्यवस्था में एक नए विभाजन को जन्म दिया। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए और वैश्विक समुदाय से रूस की निंदा करने का आह्वान किया। इस संदर्भ में, भारत की प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। एक ओर, भारत ने रूस की आक्रामकता की स्पष्ट निंदा नहीं की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा महासभा में प्रस्तावों पर मतदान से विरत रहा; दूसरी ओर, उसने रूस से कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की और रक्षा सहयोग जारी रखा । भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि "यूरोप को यह मानसिकता बदलनी होगी कि उसकी समस्याएँ दुनिया की समस्याएँ हैं, पर दुनिया की समस्याएँ यूरोप की नहीं" । यह वक्तव्य भारत की उस स्थिति को रेखांकित करता है जो यूरोकेंद्रिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है और अपनी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है।

यह शोध पत्र रूस-यूक्रेन युद्ध के भारतीय विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि भारत ने इस संकट के प्रति जो रुख अपनाया, वह उसकी विदेश नीति की दीर्घकालिक परंपराओं जैसे 'रणनीतिक स्वायत्तता', 'गुटनिरपेक्षता' की विरासत, और 'बहु-संरेखण' से किस प्रकार संबंधित है । साथ ही, यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि इस रुख ने भारत की वैश्विक स्थिति, विशेष रूप से 'वैश्विक दक्षिण के नेता' और 'शांति स्थापक' के रूप में उसकी भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया है ।

यह शोध इस मान्यता पर आधारित है कि भारत की प्रतिक्रिया को केवल 'तटस्थता' या 'महाशक्तियों के बीच संतुलन' के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह उसकी 'आदेश-कथा' का सामरिक उपयोग है, जो उसे अपनी पहचान, हितों और आकांक्षाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में सहायता करता है ।

शोध उद्देश्य :

1. रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रति भारत की विदेश नीति के प्रमुख आयामों (राजनयिक, आर्थिक, सैन्य) का विश्लेषण करना और यह समझना कि ये भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं।
2. युद्ध के कारण भारत-रूस संबंधों (विशेषकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में) में आए परिवर्तनों का मूल्यांकन करना और यह आकलन करना कि क्या ये संबंध दीर्घकालिक रूप से स्थिर हैं ।
3. भारत-अमेरिका/पश्चिमी संबंधों पर युद्ध के प्रभाव का अध्ययन करना, विशेष रूप से द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम और व्यापार साझेदारी पर इसके निहितार्थ को समझना ।
4. 'वैश्विक दक्षिण के नेता' और संभावित 'शांति स्थापक' के रूप में भारत की भूमिका पर इस संकट के प्रभाव का आकलन करना ।

परिकल्पनाएँ :

1. H1: रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया 'बहु-संरेखण' की उसकी नीति की निरंतरता है, जो 'गुटनिरपेक्षता' की विरासत पर आधारित है, न कि उससे विच्छेद। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है।

2. H2: रूस के साथ ऐतिहासिक रणनीतिक संबंध और रक्षा निर्भरता भारत की स्थिति के प्रमुख कारक हैं। युद्ध के बावजूद, रक्षा सहयोग में गिरावट के बावजूद, भारत रूस को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता रहेगा।

3. H3: रूस से सस्ते तेल के आयात ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, लेकिन इससे पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में तनाव पैदा हुआ है और द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम बढ़ा है, जिससे भारत को एक जटिल संतुलन अभ्यास करना पड़ रहा है।

4. H4: भारत की 'तटस्थ' स्थिति ने उसे 'वैश्विक दक्षिण' के नेता के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर दिया है, लेकिन 'सिद्धांतों' (संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता) और 'हितों' के बीच विसंगति ने उसकी अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को चुनौती दी है।

साहित्य समीक्षा :

रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत की विदेश नीति पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है, जिसे चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

(क) भारत की 'तटस्थता' और 'रणनीतिक स्वायत्तता' की अवधारणा: अधिकांश विद्वान भारत के रुख को 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' (एन.ए.एम.) की विरासत से जोड़ते हैं। फोमिन और क्रायुचकोवा (2025) तर्क देते हैं कि भारत का प्रतिबंधों के प्रति दृष्टिकोण नेहरूवादी परंपरा और व्यावहारिकता के मिश्रण से विकसित हुआ है। बार्थवाल-दत्ता (2026) भारत की प्रतिक्रिया को 'आदेश-कथा' के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहाँ भारत स्वयं को 'वैश्विक दक्षिण का नेता', 'अर्थव्यवस्था का डी-रिस्कर', और 'स्थिरीकरण बल' के रूप में चित्रित करता है। मुखर्जी (2025) भारत के रुख को 'संप्रभुता विरोधाभास' कहते हैं, जहाँ एक देश जो संप्रभुता का सम्मान करने का दावा करता है, उसने रूसी आक्रमण के मामले में नैतिक सिद्धांतों पर रणनीतिक तटस्थता को प्राथमिकता दी। वर्मा (2025) भी इस विरोधाभास को रेखांकित करते हैं कि भारत ने 'संप्रभुता-हॉक' होने के बावजूद रूस की आलोचना से परहेज़ किया।

(ख) भारत-रूस संबंधों की निरंतरता: शोधकर्ताओं ने रूस-भारत संबंधों की स्थिरता पर बल दिया है। गोरेनबर्ग एट अल. (2025) के अनुसार, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ा है, जबकि सैन्य-तकनीकी सहयोग में कुछ गिरावट आई है । आईआईएसएस (2024) की रिपोर्ट बताती है कि भारत की रूस पर रक्षा निर्भरता (घटकर 36% हुई) और तेल आयात उसके रुख के प्रमुख कारक हैं । मेघवाल और कुमार (2025) रियलिस्ट ढांचे में इस संबंध को राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन के संदर्भ में विश्लेषित करते हैं ।

(ग) आर्थिक कारक और पश्चिमी दबाव: साहित्य में रूसी तेल आयात के आर्थिक लाभ और पश्चिमी दबाव के बीच तनाव पर चर्चा हुई है । इंडियन एक्सप्रेस (2026) में प्रकाशित एक लेख में तर्क दिया गया कि भारत ने 'ऊर्जा सुरक्षा' के बहाने रूसी आक्रामकता पर चुप्पी साधी, परंतु अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए उसी 'अपरिहार्य' निर्भरता का त्याग कर दिया जिससे उसकी वैश्विक विश्वसनीयता को ठेस पहुँची । द फ्राइडे टाइम्स (2026) का एक दृष्टिकोण यह भी है कि 'हित-प्रथम' की इस नीति ने पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी को मध्यस्थता जैसे महत्वपूर्ण राजनयिक अवसर प्रदान किए ।

(घ) 'वैश्विक दक्षिण' का नेतृत्व और शांति स्थापक की भूमिका: साहा (2025) और पांडा (2025) भारत की शांति स्थापक बनने की क्षमता पर चर्चा करते हैं । चंद्रा (2024) का तर्क है कि भारत अब निष्क्रिय तटस्थता से आगे बढ़कर वैश्विक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है । हालाँकि, इवानेक (2025) जैसे विद्वान भारतीय सामरिक समुदाय में रूस की सैन्य क्षमताओं और युद्ध की प्रकृति को लेकर मिश्रित धारणाओं पर प्रकाश डालते हैं ।

साहित्य समीक्षा से पता चलता है कि भारत की प्रतिक्रिया को समझने के लिए ऐतिहासिक विरासत, भू-राजनीतिक हितों और नैतिक दावों - तीनों स्तरों पर विश्लेषण आवश्यक है।

शोध पद्धति :

अध्ययन का प्रकार: यह एक गुणात्मक केस स्टडी है जो भारत की विदेश नीति पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण करती है। यह शोध आलोचनात्मक विवेचनात्मक विश्लेषण और नीति विश्लेषण के मिश्रण पर आधारित है।

आंकड़ों के स्रोत : इस शोध में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है:

· **शैक्षणिक पत्रिकाएँ:** पीयर-रिव्यूड जर्नल (जैसे, इंडिया रिव्यू, इंटरनेशनल अफेयर्स , जर्नल ऑफ एशियन सिक्योरिटी) में प्रकाशित लेख ।

· **थिंक-टैंक रिपोर्ट्स:** प्रमुख संस्थानों (जैसे, आईआईएसएस, सीएनए, एमपी-आईडीएसए) द्वारा प्रकाशित विश्लेषण ।

· **सरकारी वक्तव्य और अधिकारियों के बयान:** भारतीय विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, और अन्य अधिकारियों के सार्वजनिक भाषण एवं बयान ।

· **समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ:** विश्वसनीय मीडिया स्रोत (जैसे, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू, ग्लोबल पॉलिसी जर्नल) ।

विश्लेषण की विधि: एकत्रित आंकड़ों का विषय-वस्तु विश्लेषण किया गया है। निम्नलिखित मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

1. भारत का राजनयिक रुख (संयुक्त राष्ट्र में मतदान, वक्तव्य)।
2. भारत-रूस आर्थिक एवं रक्षा सहयोग में परिवर्तन।
3. भारत-पश्चिमी देशों के संबंधों पर प्रभाव।
4. 'वैश्विक दक्षिण' और 'शांति स्थापक' के रूप में भारत की आत्म-प्रस्तुति।

सीमाएँ: यह शोध पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर है। प्राथमिक स्रोतों (जैसे, नीति-निर्माताओं के साथ साक्षात्कार) का अभाव इसकी सीमा है। साथ ही, युद्ध अभी जारी है, अतः निष्कर्ष प्रारंभिक और परिवर्तनशील हैं।

परिणाम :

विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए:

- राजनयिक मोर्चा: भारत ने 21 में से 20 संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान से विरत रहा, जिसमें रूस की निंदा की गई थी । प्रधानमंत्री मोदी ने 'आज का युग युद्ध का नहीं है' का नारा दिया और शांति वार्ता का आह्वान किया ।
- आर्थिक संबंध (भारत-रूस): भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 2022 में 0.2% से बढ़कर 2024 में 40% से अधिक हो गया । द्विपक्षीय व्यापार में 30% से अधिक की वृद्धि हुई ।
- रक्षा संबंध: रूस से भारत के रक्षा आयात में गिरावट आई है (70% से घटकर 36%), परंतु संयुक्त उत्पादन और लाइसेंस निर्माण जारी है ।
- भारत-पश्चिमी संबंध: अमेरिका ने रूसी तेल व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और भारतीय आयातों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी ।

'वैश्विक दक्षिण' और शांति स्थापक की भूमिका: भारत ने दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा, यूक्रेन को मानवीय सहायता दी, और जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र को लेकर रूस से बातचीत की। मोदी ने जुलाई 2024 में मॉस्को और अगस्त में कीव का ऐतिहासिक दौरा किया।

निष्कर्ष :

1. परिकल्पना H1 (पुष्ट): भारत की प्रतिक्रिया 'रणनीतिक स्वायत्तता' और 'बहु-संरेखण' की नीति की निरंतरता है, जो 'गुटनिरपेक्षता' की विरासत पर आधारित है। भारत ने किसी भी महाशक्ति खेमे का पूर्ण समर्थन न करके अपनी नीति-निर्माण की स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

2. परिकल्पना H2 (आंशिक रूप से पुष्ट): रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध और रक्षा निर्भरता महत्वपूर्ण कारक हैं। युद्ध के बावजूद, राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन रक्षा-तकनीकी सहयोग में गिरावट के संकेत हैं। भारत अपनी रक्षा आपूर्ति का विविधीकरण कर रहा है।

3. परिकल्पना H3 (पुष्ट): सस्ते रूसी तेल ने ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई, परंतु पश्चिमी प्रतिबंधों के जोखिम ने अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव उत्पन्न किया है। भारत को 'हित' और 'सिद्धांत' के बीच एक कठिन संतुलन अभ्यास करना पड़ रहा है।

4. परिकल्पना H4 (आंशिक रूप से पुष्ट): 'वैश्विक दक्षिण के नेता' के रूप में भारत की पहचान मजबूत हुई है, लेकिन 'संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता' और 'रूसी आक्रामकता पर मौन' के बीच विसंगति ने उसकी विश्वसनीयता को चुनौती दी है। भारत की 'शांति स्थापक' की भूमिका अभी परीक्षण के दौर में है।

विवेचना :

रूस-यूक्रेन युद्ध ने भारतीय विदेश नीति के बुनियादी तनावों को उजागर किया है, सिद्धांत बनाम हित, स्वायत्तता बनाम संरेखण, और क्षेत्रीय शक्ति बनाम वैश्विक नेता के बीच संतुलन।

भारत की प्रतिक्रिया को एक 'आदेश-कथा' के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ वह न केवल बाहरी दबाव का सामना करती है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था की शर्तों को पुनः परिभाषित करने का प्रयास करती है। 'वैश्विक दक्षिण' की बयानबाजी और यूरोकेंद्रिक विश्वदृष्टि की आलोचना भारत की उस महत्वाकांक्षा को दर्शाती है जो वह पश्चिमी प्रभुत्व वाली व्यवस्था के विकल्प के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना चाहता है।

हालाँकि, इस रणनीति की लागत भी है। जहाँ एक ओर रूस से सस्ते तेल ने भारत को आर्थिक स्थिरता प्रदान की, वहीं इसने उसे अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम में डाल दिया। 'ऊर्जा सुरक्षा' के तर्क ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक 'मूल्य-आधारित' खिलाड़ी के बजाय एक 'हित-आधारित' खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है।

इस स्थिति ने भारत की 'वैश्विक दक्षिण' के नेता के रूप में भूमिका को जटिल बना दिया है। एक ओर, कई विकासशील देश भारत के इस रुख को पश्चिमी दबाव के खिलाफ 'प्रतिरोध' के रूप में देखते हैं ; दूसरी ओर, 'संप्रभुता' और 'क्षेत्रीय अखंडता' के सिद्धांतों की अवहेलना (चूँकि रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया) ने भारत को नैतिक संकट में डाल दिया है।

भारत की 'शांति स्थापक' की भूमिका अभी परीक्षण के दौर में है। यद्यपि मोदी ने दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा, भारत अभी तक कोई ठोस शांति पहल शुरू नहीं कर पाया है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए पश्चिमी चिंताओं को कैसे संबोधित करता है और साथ ही 'सिद्धांतों' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कैसे सिद्ध करता है।

निष्कर्ष :

रूस-यूक्रेन युद्ध ने भारतीय विदेश नीति के लिए एक गंभीर परीक्षा का क्षण प्रस्तुत किया है। भारत ने 'रणनीतिक स्वायत्तता' और 'बहु-संरेखण' के अपने ऐतिहासिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा दिखाई है, जो 'गुटनिरपेक्षता' की विरासत से प्रेरित हैं। अपनी 'आदेश-कथा' के माध्यम से, भारत ने न केवल पश्चिमी दबाव का विरोध किया, बल्कि स्वयं को 'वैश्विक दक्षिण' के नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी किया।

हालाँकि, इस नीति की लागत भी रही है। 'सिद्धांत' (संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता) और 'हित' (सस्ता तेल, रूसी रक्षा उपकरण) के बीच विसंगति ने भारत की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को चुनौती दी है। भारत ने दिखा दिया है कि वह 'हित' के आगे 'सिद्धांत' को लचीला बना सकता है, जिससे उसकी 'मूल्य-आधारित' विदेश नीति की छवि धूमिल हुई है।

भविष्य के लिए, भारत को एक नाजुक संतुलन बनाना होगा: रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखना, पश्चिमी प्रतिबंधों के जोखिम को कम करना, और 'वैश्विक दक्षिण' के नेता तथा 'शांति स्थापक' के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना। युद्ध की समाप्ति और उसके बाद की वैश्विक व्यवस्था भारत की विदेश नीति की दिशा तय करेगी। भारत को अब 'तटस्थता' से आगे बढ़कर एक 'रचनात्मक मध्यस्थ' की भूमिका निभानी होगी, जो युद्ध की समाप्ति और दीर्घकालिक शांति के लिए ठोस कदम उठा सके।

संदर्भ :

1. बार्थवाल-दत्ता, एम. (2026). नैरेटिंग ऑर्डर ऐज़ रेज़िस्टेंस: इंडिया, द ईयू, एंड द 'रशिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट'. *इंडिया रिव्यू.*
2. मुखर्जी, ए. (2025). इंडियाज़ सोवरेनिटी पैराडॉक्स: न्यूट्रैलिटी, ऑयल, एंड द प्राइस ऑफ मल्टी-अलाइनमेंट. *यूरोपियन कंसोर्टियम फॉर पॉलिटिकल रिसर्च (ई.सी.पी.आर.) द लूप.*
3. गोरेनबर्ग, डी., एडमंड्स, जे., वालर, जे., क्यूसिक, जे., एवं ईवलेथ, डी. (2025). रशिया-इंडिया रिलेशन्स: मल्टीपोलैरिटी इन प्रैक्टिस? *सीएनए नेशनल सिक्योरिटी एनालिसिस.*
4. साहा, ए. (2025). कैन इंडियाज़ पीस-मेकिंग रोल इन द यूक्रेन क्राइसिस कंसॉलिडेट हर लीडरशिप पोज़िशन ऑन द ग्लोबल स्टेज? *सेज जर्नल.*
5. मेघवाल, एस., एवं कुमार, आर. (2025). इंडिया-रशिया डायनेमिक रिलेशन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. *अर्था जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज़, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी।*
6. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (आई.आई.एस.एस.). (2024). इंडियाज़ रिलेशनशिप विद रशिया. *स्ट्रैटेजिक कमेंट्स, 30(19).*
7. वर्मा, आर. (2025). इंटरेस्ट्स ट्रम्प प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़: इंडियाज़ न्यूट्रैलिटी इन द रशिया-यूक्रेन वॉर. *इन रूटलेज बुक.*
8. *द इंडियन एक्सप्रेस.* (2026, 6 फ़रवरी). इंडिया, रशिया, एंड द कॉस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी इन ट्रेड डील विद यूएस.
9. फोमिन, एम. वाई., एवं क्र्युचकोवा, ए. ए. (2025). इंडियाज़ अप्रोच टू सैंक्शन्स: द ओरिजिन्स, करंट स्टेट एंड सिग्निफिकेंस फॉर द ग्लोबल साउथ. *रशिया इन ग्लोबल अफेयर्स, 23(2), 165–179.*
10. *द फ्राइडे टाइम्स।* (2026, 14 अप्रैल). हाउ इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर प्रॉफिट क्रिएटेड ए डिप्लोमैटिक वैक्यूम फॉर पाकिस्तान टू फिल.
11. खान, यू. पी. (2025). इंडिया बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्ट: ए केस ऑफ कन्वीनिएंट कमिटमेंट्स. *डैली औसाफ.*
12. चंद्रा, ए. (2024, 26 सितम्बर). इंडिया ऐट द क्रॉसरोड्स: रीडिफाइनिंग न्यूट्रैलिटी ऐज़ ग्लोबल लीडरशिप. *ग्लोबल पॉलिसी जर्नल.*
13. इवानेक, के. (2025). परसेप्शन ऑफ द रशियन इन्वेज़न ऑफ यूक्रेन इन द इंडियन स्ट्रैटेजिक डिस्कोर्स, 2022–2025. *सीईईओएल, 60(विशेषांक), 333–349.*
14. पांडा, जे. (2025). कैन इंडिया एडवांस पीस इन यूक्रेन? *इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी (आई.एस.डी.पी.).*

15. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. (1961). जवाहरलाल नेहरूज़ स्पीचेज़.

16. आचार्य, ए., एवं बुज़ान, बी. (सम्पा.). (2009). नॉन-वेस्टर्न इंटरनेशनल रिलेशन्स थ्योरी: पर्सपेक्टिव्स ऑन एंड बियॉन्ड एशिया. *रूटलेज.*

17. हरेल, ए. (2007). ऑन ग्लोबल ऑर्डर: पावर, वैल्यूज़, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। *ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.*

18. मिस्किमन, ए., ओ'लफलिन, बी., एवं रोज़ेल, एल. (2013). स्ट्रैटेजिक नैरेटिव्स: कम्युनिकेशन पावर एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। *रूटलेज.*

19. *द हिन्दू.* (2010). इंडिया कन्सर्न्ड ओवर यूनिलैटरल सैंक्शन्स ऑन ईरान.

20. *एनडीटीवी.* (2018). इंडिया रिकग्नाइज़ेज़ ओनली यूएन सैंक्शन्स, नॉट कंट्री-स्पेसिफिक: सुषमा स्वराज.